भाजपा की नीति: काम नहीं, केवल काम की बात करो

फ़रीदाबाद-गुड़गांव मैट्रो की चर्चा चलती रहेगी, रेल नहीं चलेगी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) कभी मंझावली पुल से जनता को होने वाले फायदों को गिनाते हैं तो कभी एफएमडीए से होने वाला लाभ और अब पिटारे से निकाल लाये हैं फरीदाबाद-गुड़गांव मैट्रो रेल। करना-धरना कुछ नहीं केवल शगूफेबाजी से ही जनता को बहलाये रखना बहुत अच्छे से आता है भाजपाईयों को।

प्रति दिन आने-जाने वाले लाखों लोगों को खुशफहमी में रखने के लिये भाजपा सरकार बीते आठ-नौ साल से गाहे-बगाहे बयानबाज़ी करती रहती है। नि:संदेह भारी यातायात के चलते इस मार्ग पर आने-जाने वालों को काफ़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सपने भाजपा सरकार जनता को दिखा रही है उनके पूरे होने की कोई सम्भावना दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही। हां, बदरपुर महरौली के रास्ते मेट्रो में फ़रीदाबाद को गुड़गांव से जोड़ने का काम निकट भविष्य में पूरा हो सकता है। विदित है कि मौजूदा पहाड़ वाली सड़क बनने से पूर्व गुड़गांव जाने का सड़क मार्ग बदरपुर से महरौली होकर ही जाने का था।

इसमें कोई दो राय नहीं कि फ़रीदाबाद-गुड़गांव को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने का स्वप्न तो मंझावली पुल वाले से भी कहीं अधिक सुहाना है। परन्तु बड़ा सवाल इस पर खर्च होने वाले 6 हजार करोड़ का है। जो खट्टर सरकार मेडिकल छात्रों की बेतहाशा फ़ीस बढ़ाने के बावजूद भी उन्हें पढ़ाने के लिये पर्याप्त फैकल्टी न दे सके, वेतन बचाने के लिये लाखों पदों को न भर सके, मेडिकल यूनिवर्सिटी को चलाने के लिये अनुदान की बजाय कर्जा देने लगे, वह सरकार 6 हजार करोड़ कहां से लायेगी?

वैसे यह भी कोई बहुत जरूरी नहीं कि इस मार्ग पर चलने वाली रेल को खंभों पर ही चलाया जाए। दरअसल खंभों पर अथवा भूमिगत चलाने की अनिवार्यता केवल वहां होती है जहां धरती पर जगह न हो। लेकिन इस मार्ग पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।

इसलिये खंभों की बजाय धरती पर भी रेलवे लाइन बिछा कर काम चलाया जा सकता है। परन्तु यहां मकसद काम चलाने का तो है नहीं, केवल शगूफेबाज़ी करने का है जो ये सियासी लोग करते रहेंगे।

इसके साथ-साथ मौजूदा सड़क मार्ग को आवारा पशुओं तथा जगह-जगह विशेषकर शहरी क्षेत्रों में अवैध कब्जों से मुक्त करके भी यात्रियों की समस्या को काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन यानी नाम मात्र को चलने वाली बसों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करके भी आसान किया जा सकता है।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब की शुरूआत

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) औद्योगिक मज़दूरों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में ईएसआई मेडिकल कॉलेज एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल करने में जुटा है। अपने ही डॉक्टरों विशेषकर स्नातकोत्तर विद्यार्थी, सीनियर रेजिडेंट इत्यादि को उनके काम में दक्ष करने के लिए स्किल लैब की शुरूआत तीन मार्च को कर दी गई है। इस लैब में डॉक्टरों को सिखाया जाएगा कि चिकित्सा के दौरान मरीज़ों का बेहतर ढंग से किस तरह इलाज करना है। पहले दिन के सत्र में हृदयाघात के मरीजों की जान बचाने के लिए सीपीआर विधि का प्रयोग डमी पर करना सिखाया गया। इसके लिए अस्पताल ने अमरीकन हार्ट एसोसिएशन के साथ गठजोड़ किया है।

इसी लैब में मरीजों पर शल्य चिकित्सा, इंजेक्शन लगाना आदि-आदि की ट्रेनिंग भी डमी पर कराई जाएगी। इन सब कामों का उद्देश्य यह है कि असली मरीजों पर कार्रवाई करने से पहले डमी पर डॉक्टर लोग अपना हाथ साफ करके दक्षता हासिल कर लें।

सीएम साहब! बातें मत बनाइए, कार्रवाई कीजिए

फरीदाबाद। मज़दूर मोर्चा औद्योगिक नगरी में विकास के नाम पर विभागों के बीच चल रही बंदरबांट की जानकारी होने पर भी कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का अधिकारियों से यह कहना कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, प्रशासन पर उनकी कमजोरी दिखाता है।

करीब आठ साल से सत्ता की बागडोर थामे मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को हुई ग्रीवांस कमेटी की बैठक में जब यह कहा कि एक विभाग के 52 बैंक खाते हैं तो वह विभाग के भ्रष्टाचार को नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाने की अपनी कमी ही उजागर कर रहे थे। उनकी बेचारगी ही कही जाए कि वह उस विभाग का नाम भी नहीं ले पाए। बैठक में एक तरफ तो उन्होंने विकास के नाम पर विभागों द्वारा धन की बर्बादी करने की बात कुबूल की, तो दूसरी तरफ घोषणा की कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। क्या सूबे के मुखिया यह कह रहे थे कि विभाग इसी तरह धन बर्बाद करते रहें और सरकार फंड उपलब्ध कराती रहेगी? क्योंकि उन्होंने बैठक में एक बार भी यह नहीं कहा कि विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार (जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि उनका मुंह न खुलवाएं) को समाप्त करेंगे या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस करेंगे। दावा किया कि अब वह एसा प्लेटफार्म तैयार करेंगे जिस पर किसी विभाग से पैसा निकालने से लेकर किसको कितना भुगतान किया गया सब एक जगह देखा जा सकेगा। सीएम साहब, राज्य में लगभग सभी विभाग ई गवर्नेंस से जुड़े हैं, बेहतर होगा कि नए प्लेटफार्म की जगह स्थापित व्यवस्था को ही आप सही ढंग से लागू करा दें। इसके लिए मुंह खोलने की नहीं, कार्रवाई करने की जरूरत होती है।

बांग्लादेश को सस्ती, हमें महंगी बिजली बेचता है अडानी

पुष्पा गुप्ता

अडानी ग्रुप जैसा घोटालेबाज ग्रुप आपको दूसरा नहीं मिलेगा... अब ख़बर आई है कि बांग्लादेश के बढ़ते दबाव के बीच अडानी की कंपनी ने बांग्लादेश को कम कीमत पर बिजली की सप्लाई देने का वादा कर दिया है, हालांकि मोदी सरकार ने 2017 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर दबाव डालकर महंगी बिजली खरीदने का समझौता कराया था लेकिन आज की परिस्थितियों में अडानी खुद मुश्किल में आ गए, अगर वे बिजली की कीमत कम नही करते तो सौदा रद्द हो जाता और अडानी बेहद मुश्किल में फंस जाते।

लेकिन जब आप जानेंगे कि यही अडानी पॉवर यहां हरियाणा और गुजरात में राज्य की बीजेपी सरकारों से मिलकर कैसे कैसे खेल कर रही है तो आपकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाएंगी।

पहले बात करते हैं हरियाणा की, क्या आप जानते हैं कि 2007 में अडानी पावर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा सरकार से करार किया था इस करार में स्पष्ट रुप से कहा गया था कि अडानी ग्रुप हरियाणा को 2.94 रुपयें प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा, ये समझोता 25 वर्षों के लिए था। बाकायदा बिजली खरीद समझौता (पीपीए) पर साइन भी हुए। और गुजरात के मुंद्रा से महेंद्रगढ़ तक अडानी पावर द्वारा बिजली की लाइन भी बिछाई गई।

लेकिन 2020 में अडानी ग्रुप ने हरियाणा को दी जाने वाली 1424 मेगावाट बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी।

इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार को अडानी ग्रुप की वजह से प्रतिदिन 140 करोड़ 50 लाख रुपये की चपत लग रही है क्योंकी एग्रीमेंट के मुताबिक अडानी की ओर से प्रदेश को बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है। ऐसे में सरकार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्राइवेट कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ेगी।

सुरजेवाला ने कहा कि अडानी पॉवर ने निश्चित दर पर 25 साल के लिए बिजली आपूर्ति का समझौता किया है और कुछ साल बाद उत्पादन लागत बढ़ने के नाम पर बिजली मंहगी करना चाहते हैं और इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में पराजित होने के बाद आप बिजली आपूर्ति बंद कर सकते हैं? इसका उत्तर नहीं है क्योंकि आपके समझौते में स्पष्ट उल्लेख है कि लागत बढ़ने का असर समझौते पर नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ईंधन की लागत में परिवर्तन या समझौते को निष्पादित करने के लिए कठिन हो जाना, पीपीए के तहत ही अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में नहीं माना जाता है। यह कारनामा अडानी पॉवर ने हरियाणा के साथ किया है और भाजपा की खट्टर सरकार पता नहीं किस भय से अडानी पॉवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और आश्चर्यजनक चुप्पी साध कर बैठी है।

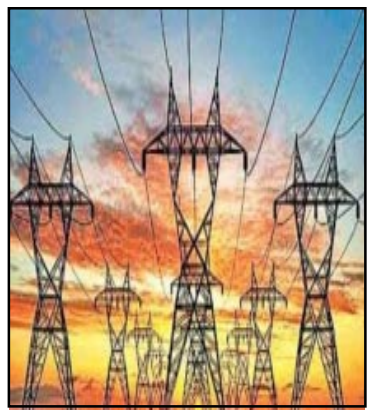

सुरजेवाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अडाणी से बिजली वापस लेने के बजाय तीन साल के लिए एमबी पावर, मध्य प्रदेश व आरकेएम पावर, छत्तीसगढ़ से 5.70 व 5.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है जिससे हरियाणा को रोज बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं जब गुजरात में विधान सभा चुनाव थे तब उल्टी सस्ती बिजली हरियाणा से गुजरात भेजी गई.

सुरजेवाला ने बताया कि नार्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुंद्रा (गुजरात), महेंद्रगढ़ (हरियाणा) की बिजली सप्लाई लाइन में 9 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 तक की रिपोर्ट में साफ है कि हर रोज औसतन 114 लाख यूनिट हरियाणा की बिजली गुजरात जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अडाणी को दी जा रही बिजली के बदले प्रदेश को राशि भी नहीं मिल रही है।

अब गुजरात मे क्या गुल खिलाए अडानी ने ये भी समझ लीजिए ! हरियाणा के जैसे ही गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) ने 2007 में अडानी पावर के साथ 2.89 रुपये और 2.35 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

लेकिन जब इंडोनेशिया से आयात होने वाले कोयले की कीमत बढ़ गई तो गुजरात सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने यहां बिजली की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी।

सरकार द्वारा अडाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) के साथ अपने बिजली खरीद से जुड़े संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तर्क दिया गया कि हमने महंगी बिजली नहीं खरीदी तो एसबीआई को बहुत नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने पॉवर कंपनियों को लोन बांटे हैं, वे दिवालिया हो जाएंगे।

गुजरात विधानसभा में यह मसला उठाते हुए कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कोयले की बढ़ी हुई दरों की आड़ में अडाणी पावर लिमिटेड को लाभ पहुंचाया है। जिसकी वजह से उसे 2,178 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया हैं। साफ़ नज़र आ रहा है कि बिना प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के ऐसे घोटाले हो ही नही सकते हैं.

अडानी के हाथो की कठपुतली न बने हरियाणा सरकार- एनआईटी विधायक नीरज शर्मा

एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि अडानी के हाथों की कठपुतली न बने हरियाणा सरकार। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि हुड्डा साहब की सरकार में अडानी से समझौता हुआ था 25 साल के लिए 2.94 पैसे में प्रतिदिन 3.5 करोड़ यूनिट बिजली देगा जोकि उसने नहीं दी। इस सरकार से हुड्डा साहब द्वारा किए गए करार को सभांला नही गया। उच्चतम न्यायलय ने भी अडानी पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है लेकिन उसके बावजूद मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट ने जुर्माना माफ कर दिया और अब सरकार सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करने जा रही है क्यों? जब पहला समझौता 2.94 पैसे का था तो सरकार अब 3.50 पैसे प्रति यूनिट खरीदने का एग्रीमेंट क्यों कर रही है। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि 224 मेगावाट बिजली छोड़ दी और उसके बदले 12-12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदी जिसके बदले सरकार को कई करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। विधायक नीरज शर्मा ने सरकार को कहा की हरियाणा के हितो को न बेचे सरकार, अडानी के हाथो की कठपुतली बनकर कोई काम करे, सरकार जनता के हितो को ध्यान में रखकर ही कार्य करे।